पुनरीक्षण सिविल

मुख्य न्यायधीश हरबंस सिंह, के समक्ष

राघवीर प्रसाद आदि,-याचिकाकर्ता।

बनाम

चेत राम,-प्रतिवादी।

1970 का सिविल पुनरीक्षण संख्या 850।

20 अप्रैल, 1971.

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम V) - आदेश 6 नियम 17 - वादी द्वारा विरासत के आधार पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर करना - वाद का संशोधन द्वारा मुकदमे के आधार को विरासत से अंतिम मालिक की वसीयत में बदलने की मांग की गई - इस तरह के संशोधन - क्या अनुमति दी जानी चाहिए - मुकदमे की स्थापना की तारीख - क्या वह तारीख होगी जब संशोधन के लिए आवेदन किया जाएगा।

यह निर्धारित किया गया है कि, जब कोई वादी अंतिम मालिक का उत्तराधिकारी होने का दावा करते हुए संपत्ति पर कब्जे के लिए मुकदमा लाता है, और बाद में उसे अपने पक्ष में वसीयत के निष्पादन के बारे में पता चलता है, जो वसीयत मुकदमा लाए जाने की तारीख पर अस्तित्व में थी, ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसे कार्रवाई के उस कारण पर फैसला सुनाए जाने से रोका जाए। यदि ऐसा वादी मुकदमे के आधार को विरासत से वसीयत में बदलने के लिए वादपत्र में संशोधन चाहता है, तो संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए। केवल यह तथ्य कि मुकदमे का कारण बदल दिया गया है, संशोधन को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। हालाँकि, संशोधित मुकदमा उस तारीख को दायर किया गया माना जाएगा जिस दिन संशोधन के लिए आवेदन दिया गया है, न कि जब मूल मुकदमा दायर किया गया था। याचिकाकर्ता ने नागरिक संहिता की धारा 115 के तहत श्री ओ. पी. गुप्ता, उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी जगाधरी, जिला अम्बाला के दिनांक 2 जून, 1970 के आदेश जिसमे उन्होंने संशोधन के लिए आवेदन खारिज कर दिया, के पुनरीक्षण ke liye आवेदन डाला है।

मनमोहन सिंह लिब्रहान, एक वकील, याचिकाकर्ताओं के लिए।

एस. के. गोयाई, वकील, प्रतिवादी के लिए ।

निर्णय

मुख्य न्यायधीश हरबंस सिंह.- (1) रघवीर पार्षद और उनकी बहन तारा वती ने चेत राम के खिलाफ विवादित घर पर कब्जा करने के लिए मुकदमा दायर किया, जो स्वामित्व के आधार पर चेत राम के कब्जे में था, जिसमें आरोप लगाया गया कि घर, वास्तव में, मूल रूप से श्रीमति कमला देवी का था, जो उनकी मृत्यु के बाद उनके पिता आत्मा राम को हस्तांतरित हो गया और आत्मा राम की मृत्यु के बाद यह वादी पक्ष को हस्तांतरित हो गया।

(2) इस मुकदमे का चेत राम ने विरोध किया, जिसने आरोप लगाया कि जब उसे एक घर से बाहर निकाल दिया गया था, जो उसके कब्जे में था, उसे विवादग्रस्त घर मिला, जो जीर्ण-शीर्ण हालत में था, उसने उस पर अपना

अधिकार कर लिया और पिछले 18 वर्षों से उस पर उसका कब्जा है और परिणामस्वरूप, 12 वर्षों से अधिक समय से खुले तौर पर इस्तेमाल करने से उसने उसे हासिल कर लिया है। उन्होंने विवाद में संपत्ति पर वादी के स्वामित्व से भी इनकार कर दिया।

(3) वादी द्वारा 8 गवाहों की जांच करने के बाद, वाद में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। यह तर्क दिया गया कि, वास्तव में, श्रीमती कमला देवी ने 9 अप्रैल, 1964 को रघवीर प्रसाद वादी संख्या 1 के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित की थी और यह तथ्य उस तारीख को वादी को ज्ञात नहीं था जब मुकदमा दायर किया गया और, परिणामस्वरूप, उन्होंने विरासत के बजाय वसीयत के तहत घर पर हक का दावा करके वाद में संशोधन की मांग की। कार्रवाई के कारण के इस परिवर्तन पर परिणामी कुछ अनुच्छेदों जैसे की " प्रतिवादी संख्या 2" शब्द का जहां भी इस्तेमाल हुआ है, उनको हटाने की भी मांग की है।

(4) इस आवेदन को खारिज कर दिया गया, यह आधार लेते हुए कि यदि संशोधन को अनुमति दी गई, तो मुकदमे की प्रकृति बदल जाएगी। इस आदेश से व्यथित होकर, वादी ने यह संशोधन दायर किया है।

(5) इसमें कोई संदेह नहीं है कि मूल रूप से वादी ने अपने मामले को विरासत पर आधारित किया है और अब वे चाहते हैं कि इस दावे को एक इच्छा के तहत बदल दिया जाए। हालाँकि, दोनों मामलों में, मुकदमे की प्रकृति कब्जे के लिए एक है और प्रतिवादी के पास कब्जे में होने के अलावा कोई शीर्षक नहीं है। मूल रूप से और अब दोनों वादी का मामला यह है कि घर श्रीमती कमला देवी का था और मूल रूप से यह दावा किया गया था कि विरासत के रूप में यह दोनों वादी को मिला था और अब यह कहा गया है कि वसीयत के आधार पर इसका स्वामित्व केवल वादी नंबर 1 के पास था।

(6) प्रतिवादी के विद्वान वकील ने दृढ़ता से आग्रह किया कि यदि इसमें कार्रवाई के कारण में परिवर्तन शामिल है तो किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने जय राम-मनोहर लाल बनाम नेशनल बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई, गुड़गांव[1] मामले में सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम प्राधिकार को इस आधार पर अलग किया कि यह एक ऐसा मामला था जहां मांगा गया संशोधन केवल औपचारिक प्रकृति का था। यह एक ऐसा मामला था जहां वादी, जो एक संयुक्त हिंदू परिवार का प्रबंधक था और व्यवसाय नाम के तहत अपना व्यवसाय चला रहा था, उस व्यवसाय नाम पर एक मुकदमा लाया। जब एक आपत्ति ली गई, तो उन्होंने यह कहते हुए वादी में संशोधन की मांग की कि उन्होंने स्वयं दायर करने का इरादा किया था और वास्तव में परिवार की ओर से व्यवसाय के नाम पर कार्रवाई दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य ने न केवल यह देखा कि इस संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए थी, बल्कि यह माना गया कि ऐसे मामले में, जहां वादी का केवल गलत वर्णन किया गया था; यदि वादपत्र में वास्तविक वादी को प्रतिस्थापित करके संशोधन किया जाता है, तो वादपत्र को मूल रूप से प्रस्तुत किए जाने की तारीख पर अपने संशोधित रूप में स्थापित किया गया माना जाएगा और परिसीमा का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(7) हालाँकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से, उपर्युक्त निर्णय में की गई सामान्य टिप्पणियों पर भरोसा किया गया है। रिपोर्ट के पैराग्राफ 5 में उनके आधिपत्य ने इस प्रकार कहा: –

[1] A.I.R 1969 SC. 1267

" ..... प्रक्रिया के नियमों का उद्देश्य न्याय प्रशासन को आसान बनाना है। किसी पक्ष को केवल कुछ गलती, लापरवाही, असावधानी या यहां तक कि प्रक्रिया के नियमों के उल्लंघन के कारण राहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय हमेशा किसी पक्ष की याचिका में संशोधन करने की अनुमति देता है, जब तक कि वह संतुष्ट न हो कि आवेदन करने वाला पक्ष दुर्भावनापूर्ण कार्य कर रहा था, या अपनी गलती से, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को चोट पहुंचाई थी जिसमे कि लागत के एक आदेश द्वारा मुआवजा नहीं दिया जा सकता। चाहे पहली चूक कितनी ही लापरवाहीपूर्ण या लापरवाही क्यों न रही हो, और, हालांकि, प्रस्तावित संशोधन में देरी क्यों न हुई हो, संशोधन की अनुमति दी जा सकती है यदि इसे दूसरे पक्ष के साथ अन्याय किए बिना किया जा सकता है। जहां तक कार्रवाई के कारण का प्रश्न है, न्यायधीश कपूर का एक निर्णय है, जैसा कि वह उस समय मेसर्स वेइकन्स मेयर एंड कंपनी, जालंधर बनाम ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रार, बॉम्बे एवम अन्य[2] के मामले में था जिसका दूसरा शीर्ष-नोट (यदि) निम्नलिखित शब्दों में है; –

"पहली चूक चाहे कितनी ही लापरवाहीपूर्ण या लापरवाह क्यों न रही हो और प्रस्तावित संशोधन में चाहे कितनी भी देर क्यों न हुई हो, यदि यह दूसरे पक्ष के साथ अन्याय किए बिना किया जा सकता है तो संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए। इसमें कोई अन्याय नहीं है अगर दूसरे पक्ष को लागत से मुआवजा दिया जा सकता है। एक वादी कार्रवाई का एक नया कारण जोड़ सकता है और प्रतिवादी एक नया बचाव जोड़ सकता है। यहां तक कि एक नए मामले को भी पेश करने की अनुमति दी जा सकती है।"

(9) इस प्रकार, केवल तथ्य, कि कार्रवाई का कारण बदल दिया गया है, संशोधन को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है।

(10) करतार सिंह वजीर सिंह बनाम सरदारा सिंह वजीर सिंह[3] मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले का संदर्भ दिया गया था। हालाँकि, यह एक ऐसा मामला था जहाँ मुकदमे को निचली अदालत के साथ-साथ निचली अपीलीय अदालत में भी खारिज कर दिया गया था और नियमित दूसरी अपील में इसमें संशोधन के लिए अनुरोध किया गया था। वादपत्र, जिसके लिए पूरे मामले की नए सिरे से सुनवाई की आवश्यकता होती। प्रत्येक मामले के तथ्यों को यह तय करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए कि संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं।
(11) उस पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने वैधानिक अवधि से अधिक समय तक प्रतिकूल कब्जे में रहकर समय की चूक से अधिग्रहण किया है। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि यहां तक कि वादी भी श्रीमती कमला देवी के साथ अपना संबंध दिखाने में विफल रहे हैं और यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि वसीयत असली या जाली है। यह योग्यता का प्रश्न है। जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, वादी नंबर 1 ने अपनी बहन के साथ विरासत के आधार पर घर पर दावा किया है। यदि उन्हें बाद में वसीयत के निष्पादन के बारे में पता चला और मुकदमा दायर होने की तारीख पर कौन सी वसीयत अस्तित्व में थी, तो कोई कारण नहीं है कि उन्हें कार्रवाई के उस कारण पर निर्णय लेने से रोका जाए। जहां तक उसके द्वारा किए गए खर्चों का संबंध है, प्रतिवादी को पूरी तरह से लागत का मुआवजा दिया जा सकता है।

---

[2] 1952 P.L.R. 176.
[3] A.I.R 1960 Pb. 255

(12) केवल एक और बिंदु है और वह सीमा के संबंध में है। प्रतिवादी की ओर से आग्रह किया गया था कि यदि संशोधन आवेदन दिए जाने पर कोई नया मुकदमा लाया गया था, तो वह यह आरोप लगाकर मुकदमे का विरोध कर सकता था कि उस तिथि तक उसका प्रतिकूल कब्जा एक अच्छे शीर्षक में परिपक्व हो गया था। वैधानिक अवधि की समाप्ति से और यदि संशोधित मुकदमा उस तारीख को दायर किया गया माना जाता है जिस दिन मूल मुकदमा दायर किया गया था, तो उसे परिसीमा की रक्षा से वंचित होने के कारण अपूरणीय क्षति होगी।

(13) मुझे लगता है कि इस बिंदु में बल है और चूंकि न्यायालय कुछ नियमों और शर्तों पर संशोधन की अनुमति दे सकता है, इसलिए मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं, नीचे दिए गए न्यायालय के आदेश को रद्द करता हूं और संशोधन की लागत के रूप में 200 रुपये के भुगतान पर अनुमति देता हूं। मैं आगे निर्देश देता हूं कि संशोधित मुकदमा उस तारीख को दायर किया गया माना जाएगा जिसमें संशोधन हेतु आवेदन दिया गया था। पक्षों को 17 मई, 1971 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है, जिस तारीख को रु. 200, दी गई लागत का भुगतान किया जाएगा। यदि लागत का भुगतान कर दिया गया है, प्रार्थना के अनुसार संशोधन की अनुमति दी जाएगी। वादी को संशोधित वाद दाखिल करने के लिए समय दिया जाएगा और उसके बाद प्रतिवादी को लिखित बयान देने के लिए समय दिया जाएगा। नए मुद्दों का निपटारा किया जाएगा और पक्षों की सहमति से पहले से दिए गए सबूतों को मामले में सबूत माना जा सकता है। पक्षों को मामले में उत्पन्न होने वाले नए मुद्दों पर साक्ष्य का नेतृत्व करने का अवसर दिया जाएगा। मामले का शीघ्र निर्णय किया जाएगा। ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड नहीं भेजे गए। इस फैसले की एक प्रति तुरंत ट्रायल कोर्ट को भेज दी जाएगी। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसके उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेशयों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त होगा।

सरू गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पानीपत, हरियाणा